GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No. *17
TO BE ANSWERED ON 05.02.2024

MSME CONTRIBUTION TO GDP

*17. SHRI RAGHAV CHADHA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of MSME Gross Value Added in the country's GDP over the last three years;
(b) whether a declining trend has been observed over the last three years;
(c) whether there has been a reduction in the share of MSME products in the country’s total exports; and
(d) if so, reasons therefor and the measures taken by Government to incentivise MSMEs?

ANSWER

MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI NARAYAN RANE)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No. 17 FOR ANSWER ON 05.02.2024

(a) & (b): As per the latest information received from the Ministry of Statistics & Programme Implementation, share of MSME Gross Value Added (GVA) in all India GDP during the last 3 years is as follows:

Year	Share of MSME GVA in All India GDP (in %)
2019-20	30.5%
2020-21	27.2%
2021-22	29.1%

The share of MSME GVA in all India GDP increased from 27.2% in 2020-21 to 29.1% in 2021-22.

(c): As per the information culled out from the Data Dissemination Portal of Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS), the share of export of MSME specified products in all India exports for the year 2022-23 was 43.59% and this share has increased to 45.83% in 2023-24 (up to Nov.2023).

(d): To increase the contribution of MSMEs in exports and enhance their competitiveness, Government has taken various initiatives under Make in India Programme, Promotion of Ease of Doing Business, and improved availability of credit.

Moreover, this Ministry is implementing the International Cooperation (IC) Scheme, which facilitates the participation of MSMEs in international exhibitions, trade fairs and buyer-seller meets in foreign countries by reimbursing cost incurred on airfare, stall charges, advertisement, publicity etc. The scheme provides opportunities to MSMEs to continuously update themselves to meet the challenges emerging out of changes in technology, changes in demand, emergence of new markets etc.

Further, under the new component of IC Scheme namely Capacity Building of First Time Exporters (CBFTE) launched in June 2022, reimbursement is provided to the first time Micro & Small exporters on exports shipments, whose IEC code/registration is not more than 3 years for costs incurred on Registration-cum-Membership Certification (RCMC) with EPCs, Export Insurance Premium and Testing & Quality Certification for exports. These interventions under IC Scheme assist the exporters in MSME sector to increase their access in international markets.

The Ministry of MSME has established 59 Export Facilitation Centers (EFCs) across the country with an aim to provide requisite mentoring and handholding support to Micro and Small Enterprises (MSEs).

The Ministry is also engaged in regular inter-ministerial collaborations for strengthening and facilitating the MSMEs at the grass root level to make them more competitive and accelerate their growth in the global markets.

****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *17

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2024

जीडीपी में एमएसएमई का योगदान

***17. श्री राघव चड्ढा :**

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में देश के जीडीपी में एमएसएमई द्वारा सकल मूल्य संवर्धन में योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है;

(ग) क्या देश के कुल निर्यात में एमएसएमई उत्पादों की हिस्सेदारी में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नारायण राणे)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 17, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2024 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) : सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान अखिल भारत जीडीपी में एमएसएमई सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का हिस्सा निम्नानुसार है:

वर्ष	**अखिल भारत जीडीपी में एमएसएमई जीवीए का हिस्सा (%)**
2019-20	30.5%
2020-21	27.2%
2021-22	29.1%

अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई जीवीए की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 27.2% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 29.1% हो गई है।

(ग) : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डेटा प्रसार पोर्टल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात का हिस्सा 43.59% था और यह हिस्सा बढ़कर वर्ष 2023-24 (नवम्बर, 2023 तक) में 45.83% हो गया है।

(घ) : निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ाने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, व्यवसाय की सुगमता के संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार के लिए विभिन्न पहलें की हैं।

इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो हवाई किराया, स्टॉल प्रभार, विज्ञापन, प्रचार आदि पर खर्च की गई लागत की प्रतिपूर्ति करके एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। यह योजना एमएसएमई को प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, नए बाजारों के उद्भव, आदि से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को लगातार अपडेट करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, जून 2022 में शुरू की गई आईसी योजना के नए घटक अर्थात् पहली बार के निर्यातकों का क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) के तहत, नए सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को निर्यात शिपमेंट पर प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जिनका ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता (आरसीएमसी), निर्यात के लिए निर्यात बीमा प्रीमियम तथा परिक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर किए गए व्यय के लिए आईईसी कोड/पंजीकरण 3 वर्ष से अधिक नहीं है, की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। आईसी योजना के तहत ये इंटरवेंशन एमएसएमई क्षेत्र में निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहुंच को बढ़ाने में सहायता प्रदान करते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित सलाह और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 59 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं।

मंत्रालय जमीनी स्तर पर एमएसएमई को मजबूती प्रदान करने और सुविधा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग में भी कार्य कर रहा है ताकि उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और वैश्विक बाजारों में उनके विकास में तेजी लाई जा सके।

****

श्री राघव चड्ढा: उपसभापति महोदय, मेरा पहला सवाल भारत देश के एमएसएमई सेक्टर में जो sickness है, उससे संबंधित है। मेरा सवाल बड़ा सरल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 13,000 एमएसएमईज़ बंद हुईं, जो पिछले चार वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक हैं। अगर हम यह अनुमान लगाएं कि 50 लोग एक एमएसएमई में भर्ती होकर काम करते हैं, रोजगार लेते हैं, तो अगर 13,000 यूनिट्स बंद होती हैं, तो लगभग साढ़े छह लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापतिः आप अपना सवाल पूछिए।

श्री राघव चड्ढा: एक फैक्ट और देकर मैं अपना सवाल पूछ रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में भारत देश के जितने एक्सपोर्ट्स होते थे, उनका 50 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई सेक्टर से आता था। आज वह 50 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत हो गया है। यानी एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स भी गिरते जा रहे हैं।

श्री उपसभापतिः आप सवाल पूछिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि MSME सैक्टर की ग्रोथ तो छोड़िए, उसमें जो गिरावट देखी जा रही है, उसके क्या कारण हैं और खासकर उसका रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री नारायण राणे): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि MSME सैक्टर के अंदर 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 में जीडीपी में गिरावट आई है, ऐसा उनका कहना है, उन्होंने वैसा ही एक्सपोर्ट के बारे में भी कहा है। सर, एक्सपोर्ट दो साल में कोरोना के कार्यकाल में और जीडीपी भी कोरोना के कार्यकाल में टू परसेंट से गिरा, यह बात सही है, मगर 2021-22 में फिर 29.1 परसेंट वापस इन्क्रीज़ हुआ और 2022-23 में तो above 30 परसेंट हो ही गया होगा। कोरोना के कार्यकाल में गिरावट हुई, यह मैं मानता हूं, एक्सपोर्ट भी कम हुआ, यह भी मैं मानता हूं, मगर अभी एक्सपोर्ट भी 45.83 परसेंट हो गया है, तो वह भी इन्क्रीज़ हो रहा है। कोरोना के कार्यकाल में देश के पंत प्रधान माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने उस वक्त जो योजना बनाई, उन्होंने जो क्रेडिट गारंटी योजना चालू की, उसके अंदर MSME में कम से कम 2 लाख 41 हजार MSMEs बंद हुई थीं, उनको वापस चालू करने के लिए लोन दे दिया गया, जिसके कारण अब ये 45.83 हो गया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा जीएसटी जो 2019-20 में पांच लाख करोड़ था, वह 2020-21 में 4.7 लाख करोड़ हुआ था, जो थोड़ा कम हुआ और अभी 2021-22 में बढ़कर 5.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब यह टू परसेंट एव्री ईयर बढ़ता ही जा रहा है। आपने कहा कि कोरोना के कारण गिरावट हुई थी, मगर अब MSME में अलग-अलग योजना देकर, जो उद्योग बंद थे, वे चालू हो गए हैं और वे अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। उसकी फिगर्स मैंने जीएसटी के आधार पर कही हैं।

श्री उपसभापति: राघव चड्ढा जी, संक्षेप में पूछिएगा।

श्री राघव चड्ढा: सर, माननीय मंत्री जी ने जो फैक्ट बोला है, वह गलत बोला है।

श्री उपसभापति: राघव चड्ढा जी, उसके लिए दूसरे रास्ते हैं। आप सवाल पूछिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। जहां तक एनपीए और लोन डिफॉल्ट की बात है, इस MSME के सैक्टर में यह देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोन्स लिए गए, चाहे सरकार की किसी योजना के तहत लिए गए या बैंकों से लिए गए, वे लोन डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि वह सैक्टर पूरे तरीके से पिछले तीन-चार वित्तीय वर्ष से गिरता जा रहा है। खास तौर पर भारत सरकार एक स्कीम लाई थी, जिसका नाम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम था...

श्री उपसभापति: राघव चड्ढा जी, आप सवाल पूछिए।

श्री राघव चड्ढा: सर, इसमें सरकार की अपनी रिपोर्ट बताती है कि अधिकांश हिस्सा जो लोन के माध्यम से MSME को दिया गया था, वह एनपीए हो गया है, वह डिफॉल्ट हो गया है।

श्री उपसभापति: आपका सवाल क्या है?

श्री राघव चड्ढा: सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सैक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री उपसभापति: धन्यवाद, माननीय मंत्री जी। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़।

श्री राघव चड्ढा: और खास तौर पर एनपीए को डील करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री नारायण राणे: माननीय उपसभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि कोरोना के कार्यकाल में कई उद्योग बंद हुए थे, कामगार भी चले गए थे, उस वक्त जीडीपी में जरूर गिरावट थी। उस समय लोगों ने लोन का भी रिपेमेंट नहीं किया, बहुत सारे अकाउंट्स एनपीए हो गए। इसलिए 5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना इस देश के पंत प्रधान जी ने इस डिपार्टमेंट के लिए दी। उसमें से 2 लाख, 41 हजार करोड़ उद्योगों के लिए दिए और जिनका एनपीए हुआ, उनको भी वापस लोन देने के लिए, उसकी जो एक करोड़ रुपए की लिमिट थी, उसको पांच करोड़ रुपए तक लेकर गए। सरकार ने उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया, इसलिए फिर से उत्पादन बढ़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें पहले जितना उत्पादन बढ़ा है, कुछ घाटा नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि वे सभी इंटस्ट्रीज़ फिर से चालू हो गई हैं।

SHRI S. SELVAGANABATHY: Sir, a survey has been conducted recently with inputs from 2,600 formal MSMEs of five States and the Union Territory of Puducherry. One of the two surveyed MSMEs want an instant line of credit, but, the non-availability of the short-term credit is the biggest hindrance for the MSMEs. So, I would like to request our hon. Minister to look into the demands and requests of the MSMEs.

श्री नारायण राणे: उपसभापति महोदय, जो उद्यम बंद हुए हैं, उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से लोन की व्यवस्था और मदद की गई है। मैं समझता हूं कि कहीं ओर, जहाँ कहीं भी किसी उद्यमी को दिक्कत है, उनकी हैल्प करने के लिए पीएमईजीपी से लेकर, अलग-अलग आठ-दस योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से हम मदद करेंगे। हमारी इंडस्ट्रीज़ देश का एक्सपोर्ट बढ़ाती हैं, जीडीपी बढ़ाती हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो भी करना है, वह करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए मैं यह भी कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए 5 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं और हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उनसे भी यह कहना चाहता हूं कि हम उनकी मदद करेंगे।

श्री शक्तिसिंह गोहिल: उपसभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्री जी से प्रश्न जानना चाहता हूं, क्योंकि जो written answer दिया है, उसमें कहा गया है, MSME Gross Value Added, GVA, in all India GDP और जो आंकड़े दिए हैं, उसमें यह 2019-20 में 30.05 प्रतिशत था, 2020-21 में 27.03 प्रतिशत था, 2021-22 में 29.01 प्रतिशत था। It means कि अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि यह कोरोना की वजह से हुआ है, तो कोरोना का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 2019-20 में होना चाहिए था, लेकिन तब तो यह 30.05 प्रतिशत था। क्योकि कोरोना का इम्पैक्ट उसके बाद 2021-22 में नहीं हो सकता है, तब वह कम क्यों हुआ? माननीय मंत्री महोदय, यदि आप सिर्फ बड़े उद्योगों की चिंता करेंगे, तो लघु उद्योगों का क्या होगा? ...(**व्यवधान**)...

श्री नारायण राणे: उपसभापति महोदय, लघु उद्योग जितनी संख्या में बंद हुए, वे सभी फिर से चालू हो गए, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। वे सभी फिर से चालू हो गए हैं, इसलिए उत्पादन के संदर्भ में मैंने जीएसटी के बारे में आपको जो पढ़कर बताया है, वह आज भी Rs. 5.3 lakh crores है। महोदय, यह कम नहीं हुआ है। पहले, 2019-20 में जो 5 लाख करोड़ रुपये था, वह अभी बढ़ गया है। मैं इसमें यह भी कहता हूं कि 2020-21 में जो 27.03 प्रतिशत रहा है, वह कोरोना का कार्यकाल था। इसमें कामगार फैक्टरी छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब फैक्टरीज़ चालू होने के बाद 2021-22 में जीडीपी का वह परिमाण बढ़ गया है और इसके बढ़ने के कारण देश में एमएसएमई की पूर्व परिस्थिति का निर्माण भी हुआ है।

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister about the labour welfare and employees' wellness in the MSME sector.

श्री उपसभापति: माननीय कार्तिकेय शर्मा जी, अपना सवाल फिर से पूछिए।

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Sir, I would like to ask the hon. Minister about the steps taken to ensure labour welfare and employees' wellness in the MSME sector.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री नारायण राणे: उपसभापति महोदय, काफी कदम उठाकर इन इंडस्ट्रीज़ को फिर से चालू करने की कोशिश हुई है। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं इनके बारे में सारा पढ़कर बता देता हूं।

श्री उपसभापति: आप ब्रीफ़ली बता दीजिए।

श्री नारायण राणे: निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत, व्यवसाय की सुगमता, संवर्धन और क्रेडिट की उपलब्धता में विभिन्न पहल की हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी... ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आपस में बात न करें। ...(**व्यवधान**)... माननीय मंत्री जी, सवाल यह है कि वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री नारायण राणे: क्या सवाल है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है? ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, प्लीज़ बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नारायण राणे: नहीं, नहीं ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए, आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं यह पढ़कर बता रहा हूँ कि उद्यम चालू होने से वर्कर्स की प्रॉब्लम हल होगी। ...(**व्यवधान**)... ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बंद रहेगी, तो हल होगा। ...(**व्यवधान**)... यह एक प्रॉब्लम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: वर्कर्स के वेलनेस और वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है, यह आप माननीय सदस्य को बुलाकर बता दीजिएगा। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

Q. No.19.